



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941  
No. 366] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 11 अक्टूबर, 2019

**सं. टीएमपी/46/2016-बीपीसीएल.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/46/2016-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

—

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)  
(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10 वे दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन की तरल कार्गो बर्थ में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 बीपीसीएल के मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण के 8 फरवरी 2017 के आदेश संख्या टीएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा अनुमोदित किये गये थे और 06 मार्च 2017 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 94 में अधिसूचित हुए थे। उक्त आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गयी थी।

2.2. बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने 25 फरवरी 2019 के आदेश संख्या टीएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता का 3 महीने के लिए, यानी 01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक, विस्तार किया गया था। उक्त आदेश में बीपीसीएल को सलाह दी गयी थी कि वह सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 30 जून, 2019

तक दायर करे। तत्पश्चात्, बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा 14, जून, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता का और 3 महीने के लिए, यानी 01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक, विस्तार किया गया था। उक्त आदेश में बीपीसीएल को सलाह दी गयी थी कि वह सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 30 अगस्त, 2019 तक दायर कर दे।

2.3 जब बीपीसीएल सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 30 अगस्त, 2019 तक दायर करने में असफल रहा तो बीपीसीएल को, हमारे 05 सितम्बर, 2019 के पत्र के द्वारा, तत्काल सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया।

3.1 इस पृष्ठभूमि में, बीपीसीएल ने 16 सितम्बर, 2019 के अपने पत्र संख्या बीपीसीएल/जेएनपी/ओपीएस के द्वारा यह संसूचित किया कि प्रशुल्क प्रस्ताव तैयार करने का कार्य आरम्भ हो गया है और बीपीसीएल अपना, प्रस्ताव 30 नवम्बर 2019 तक प्रस्तुत करने में सक्षम हो पायेगा।

3.2 इसलिये बीपीसीएल ने अपने मौजूदा दरमानों में 3 महीने की अवधि अर्थात् 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक, के लिए विस्तार करने का अनुरोध किया है। बीपीसीएल ने यह भी बताया है कि वह नए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप नया प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2019 या उससे पहले दायर कर देगा।

4.1. चूंकि बीपीसीएल के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो जायेगी और बीपीसीएल द्वारा ऊपर बताए गए कारणों से किये गए अनुरोध तथा प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों को 30 सितम्बर, 2019 से आगे विस्तार किया जाना उपयुक्त समझा जाता है।

4.2 तदनुसार, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता का और 3 महीने के लिए, यानी 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक, विस्तार करता है।

4.3 बीपीसीएल को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2019 तक या उससे पहले दायर कर दे।

4.4. यदि निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यासों में वीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा जो पहले पूर्व में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, वित्त (सदस्य)

[विज्ञापन-III/4/असा./252/19]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 11th October, 2019

**No. TAMP/46/2016-BPCL.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/46/2016-BPCL**

**The Bharat Petroleum Corporation Limited**

- - -

**Applicant**

### QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 10<sup>th</sup> day of October, 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the Liquid Cargo berth at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was approved by this Authority vide Order No. TAMP/46/2016-BPCL dated 8 February 2017 which was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

2.2. Based on the request of BPCL, this Authority vide its Order No. TAMP/46/2016- BPCL dated 25 February 2019 has extended the validity of the existing tariff of BPCL for a period of 3 months i.e. from 01 April 2019 to 30 June 2019. Vide the said Order the BPCL was advised to file its proposal for general revision of the tariff by 30 June 2019. Subsequently, based on the request of BPCL, again this Authority vide its Order No. TAMP/46/2016- BPCL dated 14 June 2019 has extended the validity of the existing tariff of BPCL for a further period of 3 months i.e. from 01 July 2019 to 30 September 2019. Vide the said Order the BPCL was advised to file its proposal for general revision of the tariff by 31 August 2019.

2.3. Thus, when BPCL failed to file the proposal by 31 August 2019, the BPCL was requested vide our letter dated 5 September 2019, to file its general revision proposal immediately.

3.1. In this backdrop, the BPCL vide its letter dated no. BPCL/JNP/OPS. dated 16 September 2019 conveyed that the work on formulation of tariff proposal has started and BPCL will be able to submit the working before 30 November 2019.

3.2. Therefore, BPCL has requested to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period of 3 months i.e. from 1 October 2019 to 31 December 2019. The BPCL has also stated that, the new proposal would be submitted by or before 30 November 2019 on completion as per TAMP requirements as per the new Tariff Guidelines, 2019.

4.1. Since the validity of the existing tariff of BPCL expires on 30 September 2019 and based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 30 September 2019.

4.2. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of BPCL for a further period of 3 months i.e. from 01 October 2019 to 31 December 2019, as requested by BPCL.

4.3. The BPCL is advised to file its proposal for general revision of its tariff on or before 30 November 2019, as agreed by it.

4.4. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of performance of BPCL, such additional surplus will be dealt with as per Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019, for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government vide its letter no. PR-14019/20/2009-PG (pt-IV) dated 5 March 2019 and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./252/19]